हवाई जहाज से यात्रा करना सुविधाजनक नहीं होगा । इन्दौर प्रदेश का सब से बड़ा औद्योगिक, व्यावसायिक और व्यापारिक केन्द्र है, जिसके आसपास देवास, उज्जैन, नागदा तथा रतलाम प्रमुख औद्योगिक नगर हैं । इन्दौर को नई वायु सेवाओं की आवश्यकता है ।

अतएव मेरा नागरिक विमानन मंत्रालय से आग्रह है कि अगले माह से प्रारम्भ की जा रही नई बोइंग एवं एअर विमान सेवाओं में इन्दौर को सम्मिलित किया जाए तथा इन्दौर और बम्बई के बीच बदले जा रहे टाइमिंग्ज को न बदलते हुए यथावत् रखा जाए

(vi) NEED FOR FINANCIAL ASSISTANCE TO WEST BENGAL GOVERNMENT TO PROVIDE RELIEF TO NON-ASSAMESE EVACUEES FROM ASSAM

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South): Sir, the Government of West Bengal requested several times regarding the release of funds to the West Bengal Government towards reimbursement of expenditure incurred for affording temporary relief and shelter to the non-Assamese people, who have been forcibly evicted from Assam, and are now living in camps in West Bengal.

Sir, the State Government repeatedly urged upon the Central Government to provide funds to continue necessary measures for providing relief and shelter to these persons. So far, neither has any reply been sent, nor any fund released, by the Central Government.

Under these circumstances, I urge upon the Government to provide necessary financial assistance to the West Bengal Government immediately to meet the expenditure already incurred, and to be incurred, for the relief of evacuees till they can return to their homes in Asam. I also demand that the Minister should make a statement in the House in this regard.

(vii) NEED TO PUBLISH AN ANTHENTIC HINDI VERSION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, संविधान के अनुसार हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है और कुछ समय के लिए अंग्रेजी कामचलाऊ भाषा । परन्तु खेद की बात है कि हिन्दी को आज भी अंग्रेजी की सहचरी बना कर रखे जाने की चेष्टा की जा रही है ।

भारत का संविधान मूल रूप से हिन्दी में बनाना चाहिए था, लेकिन खेद की बात है कि आज तक उसका हिन्दी में ऐसा प्रमाणिक अनुवाद भी प्रकाशित नहीं किया गया, जिसे न्यायालयों और विधि जगत में मान्यता प्राप्त हो । हिन्दी के साथ इससे बड़ा और कोई अन्याय नहीं हो सकता । यह आजाद भारत एवं देश के नागरिकों के सिर पर कलंक है ।

इसी प्रकार सरकार को अन्य भारतीय भाषाओं में भी संविधान की प्रमाणिक प्रतिलिपि तयार करानी चाहिए ।

देश के प्रत्येक नागरिक के पास संविधान के प्रति गीता, रामायण, बाइबल और कुरान की तरह रहनी चाहिए । अतः इसका सस्ता संस्करण प्रकाशित कराए जाने की नितान्त आवश्यकता है ।

DEMANDS FOR GRANTS, 1981-82—*contd.*

Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Reconstruction—*contd.*

MR. CHAIRMAN: Now, Mr. Tapeshwar Singh may speak.

श्री तपेश्वर सिंह (विक्रमगंज) : सभापति महोदय, कृषि मंत्रालय की जो डिमांड यहां विचारार्थ प्रस्तुत है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं ।

सभापति महोदय : आप जरा एक मिनट बैठें ।

मैं शुरू में ही यह कह दे रहा हूं कि रूलिंग पार्टी से काफी लोगों के नाम बोलने के लिए आए हुए हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि काफी महत्वपूर्ण विभाग है और काफी लोग बोलना चाहते हैं, इसलिए दस मिनट में अपनी बात कहें तो ज्यादा लोगों को मौका मिल जाएगा।

I would like to tell that so many names from the Ruling Party are there. Therefore my request is that Members may take only 10 minutes each so that more Members will be able to make their contribution. This is my request from that point of view.

श्री मूल चन्द डागा: बिगिनिंग में तो लोग आधे आधे घंटे बोल जाते हैं, बाद में समय पर पाबन्दी लगायी जाती है। लेकिन अच्छा है, अभी भी लोग दस मिनट ही बोलें तो अच्छा रहेगा।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ): मेरा यह कहना है कि हाउस में हमारी दो तिहाई मेजारिटी है तो इधर से दो आदमी बोलने चाहिए और उधर से एक आदमी को बोलना चाहिए।

सभापति महोदय: यह ठीक है, समय का वैसे ही ध्यान रखा जाता है।

Please take your seat. We will keep that thing in mind. Every party has been allotted time. The Chair takes into consideration other factors also.

श्री तपेश्वर सिंह : मैंने सारी रिपोर्ट और आंकड़ों को देखा है और इस से मुझे सन्तोष है कि पिछले वर्षों में कृषि विभाग और कृषि विभाग के मंत्री जी जो कि डायनेमिक मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। कृषि विभाग का जितना भी इन्फ्रा-स्ट्रक्चर है चाहे वह एफ सी आई हो, चाहे एन एस सी हो या कोआपरेटिव सेक्टर हो, नाफेड हो, इन सारे के आंकड़ों को देखने से प्रतीत होता है कि काफी अच्छा काम हुआ है।

खाद की भारी कमी इस साल थी खास कर रबी के दिनों में। ऐसा लगता था खास कर बिहार में कि किसानों की खाद की आवश्यकता की हम पूर्ति नहीं कर सकेंगे। लेकिन भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की सहायता और सौजन्य से सारी परिस्थितियों पर हम काबू पा सके। बिहार का जो सिन्द्री का फर्टिलाइजर कारखाना है, बरौनी का है या नामरूप का है, ये सारे कारखाने बन्द थे और इम्पोर्टेड फर्टीलाइजर लगभग 45.48 लाख टन विदेशों से मंगा कर किसानों की आवश्यकता की पूर्ति की गई। देश में पांच हजार प्रखंड हैं। अभी तक बड़ी भारी ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है। लगभग 2900 ऐसे प्रखण्ड हैं जहां अभी तक रेल हेड नहीं है जहा कि सुविधा से माल पहुंचाया जा सके। इस तरह के अनेक प्रखण्ड बिहार में हैं जिस से कि हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट से उस की व्यवस्था करते हैं। उस में काफी कठिनाई है, लेकिन जो आवश्यकता किसानों की है उस की हम पूर्ति कर पाते हैं। मैं इस सम्बन्ध में कृषि मंत्रालय से और खास कर कृषि मंत्री महोदय से पुरजोर शब्दों में यह मांग करना चाहता हूं कि फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस को इंस्टीच्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था के रूप मे कोआपरेटिव सेक्टर के माध्यम से कराएं और कोआपरेटिव सेक्टर जिस स्टेट में सक्षम नही हो वहां सरकार स्वयं अपने और इंस्टीच्यूशंस से चाहे सिविल सप्लाईज कारपोरेशन हो चाहे एफ सी आई हो चाहे फर्टिलाइजर कारपोरेशन हो उस के माध्यम से उस के डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था कराएं।

ऐसा देखा जाता है कि काफी बड़ी संख्या में, लगभग 40 परसेंट माल प्राइवेट लोगों को देने की व्यवस्था की गई है।

बिहार के बारे में मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि प्राइवेट ट्रेड से जो खाद दी गयी है उस में बराबर शिकायत है । उस में मिलावट की शिकायत है। काफ़ी स्केयर्सिटी थी खाद की बिहार मे, खासकर नाइट्रोजन्स और यूरिया खाद की, और काफ़ी शिकायत मिली कि ब्लैक में खाद बेची जा रही है । इसलिए मैं मांग करता हूं कि फर्टिलाइजर का वितरण, चाहे कोई सी भी खाद हो, यूरिया हो, नाइट्रोजन्स खाद हो या फ़ासफेट खाद हो, इन सब का कोआपरेटिव सैक्टर के जरिये वितरण किया जाय । और जिस स्टेट की क्षमता कोआपरेटिव सैक्टर के माध्यम से वितरण करने की नहीं, वहां सरकार इंस्टीट्यूशनेलाइज करने की चेष्टा करे ।

बिहार में बड़े पैमाने पर जूट की खेती होती है । लेकिन जे०सी०आई० की जो नीति है और तरीके है, उससे हमारे किसानों को बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है क्योंकि वहां ऐसी भूमि है जैसे सहरसा, पूरनिया और कटिहार की कि जहां जूट अच्छा होता है । लेकिन जे० सी० आई० कहने के बाद भी जट का प्रोक्योरमेंट समय पर नहीं करता है जिससे किसानों को सपोर्ट प्राइस नहीं मिलती है । आज भी बिहार की कोआपरेटिव मारकेटिंग फ़ैडरेशन जी०सी०आई० के एजेन्ट के रूप में काम करती है और अभी तक लगभग 4 करोड़ रु० जे०सी०आई० बिहार की कोआपरेटिव मारकेटिंग फेडरेशन को भुगतान नहीं कर रही है ।

पिछले 3, 4 सालों में एन०सी०डी०सी० के काम में काफ़ी विस्तार हुआ है और बिहार की ओर भी इसका ध्यान गया है । बिहार में हमारी अनेक समस्यायें हैं, एन० सी०डी०सी० कोआपरेटिव सैक्टर में काफ़ी यूजफुल काम कर रही है और वर्ल्ड बैंक के सौजन्य से बिहार में भी कोल्ड स्टोरेज या और स्टोरेज की फैसिलिटीज बढ़ाने में सहायता मिल रही है । इसलिये मैं चाहूंगा एन० सी० डी० सी० और बड़े पैमाने पर प्रोसेसिंग यूनिट्स, चाहे राइस मिल हो, तेल मिल हो या एडिबिल आयल के प्रोसेसिंग का काम हो, इसको बड़े पैमाने पर कराने की व्यवस्था करे ।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि फ़र्टिलाइजर की जो प्राइस है, मैं धन्यवाद दूंगा मंत्री महोदय को फ़र्टिलाइजर प्राइस इंटरनेशनल फ़िनोमनन है, सारे विश्व में इसके दाम बढ़े है पैट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाने की वजह से, फिर भी मंत्री जी ने इसके दाम नहीं बढ़ाये है । लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के किसानों के हित को दृष्टिकोण मे रखते हुए फ़र्टिलाइजर पर कुछ सब्सिडी देने की व्यवस्था की जाय । पिछले साल बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूं कि वहां के मुख्य मंत्री जी ने फ़र्टिलाइजर पर कुछ सब्सिडी दी, 10 से लेकर 25 प्रतिशत तक, जिससे किसानों मे बड़ा उत्साह और प्रोत्साहन था । लेकिन भारत सरकार की ओर से, खासकर प्लानिंग कमीशन ने, उस पर रोक लगायी कि इसको अनुदान नहीं देना चाहिये ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से और भारत सरकार के माध्यम से रिजर्व बैंक से आग्रह करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के किसान और खासकर जो बैकवर्ड स्टेट्स है वहां के किसान और वीकर सैक्शन के भाई जो हैं वे काफ़ी सफ़रर हैं रेट आफ इंटरेस्ट के कारण । क्योंकि रिजर्व बैंक ने जो रेट रखा है जिस पर ऋण उनको दिया जाता है वह अल्टीमेट बौरोअर के पास पहुंचते पहुंचते 12, 13 परसेंट तक हो जाता है । तो भारत सरकार इस बात पर विचार करे कि कोआपरेटिव चैनल से जो ऋण मुहैया किया जाता है किसानों को उसका रेट आफ़ इंटरेस्ट कम रखा जाय । मैं जानता हूं कि रिजर्व बैंक सेशनल रेट पर देता है, फिर भी आवश्यकता है कि किसानों के हित को सर्वोपरि रखा जाय । अब जो बैंक रेट बढ़े हैं हो सकता है

[श्री तपेश्वर सिंह]

कि 15 परसेंट तक किसानों को देना पड़े, जब कि उनकी माली हालत खराब है इसलिये मैं चाहूंगा कि रेट आफ़ इंटरेस्ट में कमी की जाय । नौमिनल रेट आफ़ इंटरेस्ट पर किसानों को खास कर के वीकर सेक्शन के किसान, मजदूर, हरिजन और आदिवासी या रिक्शा पुलर्स हैं, ऐसे लोगों को नौमिनल रेट आफ़ इंटरेस्ट पर ऋण मुहैया सहकारिता क्षेत्र से किया जाय ।

सभापति महोदय, बड़े दिनों से सुनते चले आ रहे है और चर्चा भी बहुत होती है रीजनल इम्बैलेंस की, लेकिन रिजर्व बैंक के द्वारा बातें की भी जाती हैं कि इस देश में रीजनल इम्बैलेंस नहीं बढ़ने दिया जाएगा । यह भी कहा जाता है कि इकोनोमिकली जो वीकर स्टेट्स है, चाहे वह बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, आसाम हो या राजस्थान हो, यह जो फाइनेंशियल डिसीप्लीन है, यह उन्हीं स्टेट्स के लिए हैं। मैं अपने मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे रिजर्व बैंक और वित्त मंत्री से बात करके, रीजनल इम्बैलेंस को दृष्टि में रखते हुए, बिहार पोपुलेशन के हिसाब से 1/10 हिस्सा को रिप्रजेंट करता है, बिहार की पोपुलेशन 6.5 करोड़ से ज्यादा है, यदि आप वहां के आंकड़ो को देखेंगे तो आप पायेंगे कि भारत का कम से कम रुपया बिहार के विकास में, कृषि के विकास में लगे हैं। मैं इसलिए मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि रीजनल इम्बैलेंस को दृष्टिकोण में रखकर जो इकोनोमिकली और को-आपरेटिवली वीकर स्टेट्स हैं, उनके लिए मापदंड अलग रखा जाए और जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, उनके लिए मापदंड अलग रखा जाए।

सभापति महोदय, मैं थोड़ी चर्चा को-आपरेटिव के बारे में करना चाहूंगा, क्योंकि हमारा कोआपरेटिव मूवमेंट एग्रीकल्चर से मिला हुआ है। जो रिपोर्ट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने सबमिट की है, उसमें कोआपरेटिव की भी चर्चा की गई है। मैं नहीं समझता हूं कि वह पर्याप्त चर्चा है। मैं चाहता था कि उसमें कोआपरेटिव के माध्यम से कृषि के विकास के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो।

14.47 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

लेकिन जितना मैं सोचता था, जितना मैं चाहता था उतना उपबन्ध राशि का नहीं किया गया है। कोआपरेटिव सैक्टर का वर्किंग कैपिटल 17 हजार करोड़ रु० है और लगभग आज की स्थिति में सारे देश में इसकी मैम्बरशिप दस करोड़ की है और तीन लाख से ज्यादा कोआपरेटिव सोसाइटीज इस हिन्दुस्तान में, अपने देश में काम कर रही हैं। मैं बड़े जोरों से इस बात को सदन के सामने रखना चाहता हूं और खास कर अपने कृषि और सहकारिता मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, इतने बड़े पैमाने पर सहकारिता के क्षेत्र में काम चल रहा है, कि इसको स्टेट सब्जैक्ट बनाया जाए। स्टेट में आये-दिन एक-न-एक कोआपरेटिव को पोलिटिकल टूल्स के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी क्या वजह है? एक्ट में क्लीयर व्यवस्था है, तो फिर क्या वजह है कि इनका सुपर-सैशन किया जाता है, चाहे कोई भी स्टेट हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, एक ही दिन मै 12 हजार समितियों का सुपर-सैशन किया गया। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, में इस बात को बड़े जोर से कहना चाहता हूं कि, जिसकी दस करोड़ की मैम्बर शिप हो, जिसके पास 17 करोड़ रु० की पूंजी हो और जो संस्था इतने बड़े काम में लगी हुई हो, जो पीपल्स मूवमेंट आए-दिन पोलिटिकल टूल्स बन, यह देश के हित के लिए, कोआपरेटिव मूवमेंट के लिए उचित नहीं है। मैं मांग करता हूं कि इसको सैन्टर सब्जैक्ट बना दिया जाए।

अभी हाल में, उपाध्यक्ष महोदय इस देश की नेता, हमारी प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि कोआपरेटिव मूवमेन्ट को केवल डी-आफिशियलाइज ही नही करना है बल्कि डी-पालीटीकलाइज भी करना है । हम को एक ऐसा स्टेप लेना होगा जिस से कोआपरेटिव मूवमेन्ट एक मर्यादा के साथ इस देश में चल सके । विदेशों में भी इस बात की चर्चा होती है—एक बड़ी भारी संख्या है—इन्टरनेशनल कोआपरेटिव एलाएंस—जब हम वहां गये तो वहां इस बात की चर्चा हुई कि इण्डिया में कोआपरेटिव इंस्टीचूशन को पोलिटीकल-टूल बनाया जाता है । आज हिन्दुस्तान की आधे से ज्यादा कोआपरेटिवज सुपरसेशन में हैं, पोलिटीकल आधार पर नामिनेटेड बोर्ड्स है । जैसे मध्य प्रदेश में जो जनता पार्टी की सरकार थी तो जनता पार्टी वालों ने उन बोर्ड्स को बनाया, जब वहां दूसरी सरकार बनी तो उस ने फिर नये बोर्ड्स बनाये । इस लिये मै जोरदार माग करता हूं....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude. There are many Members from your Party to speak. They must also get a chance.

श्री तरेशवर सिंह : मैं केवल एक-दो प्वाइन्ट्स कह कर ही बैठ जाता हूं । कोआपरेटिव रिपोर्ट मे यह बात आई है कि चाहे नाफेड हो, एन०ई०सी०एफ० हो, इन संस्थाओं ने वीकर सैक्शन्ज, आम कन्जयूमर्स और प्रोडयूसर्ज के लिये बहुत काम किये है । चाहे ओनियन के किसानों की समस्या हो या पोटेटो के किसानों की समस्या हो, चाहे मेघालय या मिजोरम के किसानों की समस्या हो, हिमाचल प्रदेश या जम्मू-काश्मीर के एपल-प्रोडयूसर्ज की समस्या हो, हम ने सब किसानों को उचित मूल्य दिलवाया....

MR. DEPUTY SPEAKER : You have already taken 15 minutes. Please conclude. I will call the next Member. 'Co-operation' is a State subject.

श्री तरेशवर सिंह : सिर्फ एक मिनट और लूंगा ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव कानून में कई रेस्ट्रिक्टिव क्लाजेज लगा दी गई है । जैसे कोई भी पदाधिकारी दो टर्म्ज से ज्यादा नही रहेगा । हम जिन्दगी भर मिनिस्टर बने रह सकते हैं, जिन्दगी भर पार्लियामेन्ट के मेम्बर बने रह सकते है, मुनिस्पिलटी के चेयरमैन बने रह सकते हैं, लेकिन कोआपरेटिव में दो टर्म से ज्यादा नहीं रह सकते । मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस तरह की रेस्ट्रिक्टिव क्लाजेज को हटाया जाय ।

इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और आप का भी, उपाध्यक्ष महोदय, शुक्रिया अदा करता हूं ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मै कृषि मंत्रालय एवं ग्रामीण पुनर्निर्माण विभाग की मांगों का समर्थन करता हूं तथा इस सम्बन्ध में सदन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करता हूं । सब से पहले तो मैं किसानों, वैज्ञानिकों और हमारी सरकार को बधाई देना चाहता हूं—उन्होंने बहुत मेहनत करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करके हमारे देश को आत्म-निर्भर बनाया है । दूसरी बात—में यह कहना चाहता हूं—जब तक हम अपने देश में अनाज का बफर-स्टाक तैयार नहीं करेंगे तब तक न तो हम पब्लिक

डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सकसेसफुल कर सकते हैं और न हम कीमतों को कन्ट्रोल में रख सकते हैं । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रोक्योरमेन्ट पालिसी के जो टारगेट्स स्टेट्स के सामने रखे गये हैं—हमारे सभी चीफ़ मिनिस्टर उन टारगेट्स को अवश्य पूरा करें । गेहूं के मामले में, चावल के मामले में जो भी टारगेट्स फिक्स किये गये हैं उन्ह उन टारगेट्स को अवश्य पूरा करना चाहिये । अगर वे पूरा नहीं करते हैं तो न हमारा बफर-स्टाक बन सकता है और न हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल सकता है ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं—इधर दो महीनों से कीमतों में वृद्धि हो रही है । शक्कर की कीमतों में वृद्धि हुई है । हमारे राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों से, पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों से शक्कर पाकिस्तान में जाती है, जहां पर शक्कर के भाव बहुत महंगे हैं । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आप राज्य सरकारों को निर्देश दें कि वे एसेंसियल कामोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत नेशनल सेक्यूरिटी एक्ट के अन्तर्गत उन फोर्सेस के खिलाफ़ कदम उठाएं, जो स्मगलिंग करती हैं ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता कि हमारे राजस्थान में इस साल भयंकर अकाल की स्थिति है और जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, बाड़मेर और जैसलमेर का जो क्षेत्र है उसमें तीन साल से और कुछ हिस्सों में तो चार साल से लगातार अकाल की स्थिति है । उस अकाल की स्थिति को फेस करने के लिए राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है परन्तु राज्य सरकार के साधन सीमित हैं । राजस्थान सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह 95 करोड़ रुपये का डेफोसिट बजट है और रिजर्व बैंक का जो ओवरड्राफ्ट है वह 95 करोड़ रुपये का है । राजस्थान सरकार अपने साधनों से इस भयंकर संकट का मुकाबला नहीं कर सकती है । अभी आपने एक स्टडी टीम हमारे इलाके का अध्ययन करने के लिए भेजने की बात की है और वह कल या परसों वहां पहुंच जाएगी । इसके लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने स्टडी टीम समय पर भेजी है परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के पास सीमित साधन हैं और हमारे बाड़मेर और जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान की स्थिति बड़ी भयंकर है । वहां पर पानी का अकाल है और उस की एक समस्या पैदा हो गई है । वहां घास भी पैदा नहीं हुई है और इस को भी एक समस्या पैदा हो गई है । न वहां पर अनाज ही पैदा हुआ है । इन परिस्थितियों में हमारी वहां की सरकार ने 30 मार्च, 1981 को जो एक मेमोरेण्डम प्रस्तुत किया है उस मेमोरेण्डम को देखते हुए राजस्थान सरकार 7.74 करोड़ रुपये की मार्जीनल मनी और 17 करोड़ रुपये, 5 परसेन्ट एडवान्स प्लान में जुटा सकती है लेकिन और साधन नहीं जुटा सकता । इसलिए 131.52 करोड़ रुपये को जो राजस्थान सरकार ने डिमान्ड की है वह मिलनी चाहिए । जब तक 50 परसेन्ट लोन और 50 परसेंट सब्सीडी के आधार पर उन को पैसा नहीं दिया जाएगा, तब तक इस अकाल की स्थिति का राजस्थान सरकार मुकाबला नहीं कर सकती । 50 परसेन्ट लोन और 50 पर सेन्ट सब्सीडी सातवें फाइनेन्स कमीशन ने भी रिकमेंड किया है और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने उस को मान लिया है। They recommended half loan or half subsidy. वहां पर ऐसे सरकमटान्सेज हैं और लगातार दो साल से, तीन साल से अकाल

को स्थिति है और उस का मुकाबला करने के लिए उस के पास साधन नहीं है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि यह जो रिकमेन्डेशन की गई है, उस को माना जाए।

In acordance with the recommendation of the 7th Finance Commission contained in Chapter IV as communicated by Government of India vide letter No. F/43(i) PFI/79 dated 25-4-79.

50 पर सेन्ट लोन और 50 परसेन्ट सब्सीडो दी जाए तब जाकर मामला कुछ सुलझ सकता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 1974–75 में नेचुरल कैलेमिटीज को मीट 8 करने के लिए 10.19 करोड़ रुपये की राजस्थान को मदद दी जाती थी, जिस को 1977–78 में रिड्यूस करके 7.74 करोड़ रुपये कर दिया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि नेचुरल कैलेमिटीज को मीट करने के लिए जो मार्जीनल मनी पहले 10·19 करोड़ दी जाती थी, उस को महंगाई की वजह से बढ़ा कर 15 करोड़ कर दिया जाए।

मैं ड्रिंकिंग वाटर के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे डिस्ट्रिक्ट जसलमेर और बाड़मेर को प्रति व्यक्ति चौथाई गेलन पानी मिल रहा है। इतना पानी बहुत ही अपर्याप्त है। इस के लिए मिलिट्री और फोर्सिज की सहायता की आवश्यकता है। मिलिट्री ने इस काम में पहले जो मदद की थी वह बहुत ही सराहनीय थी। अब भी उस से सहायता ले कर सारे स्थानों पर पीने का पानी पहुंचाया जाए। जिन गावों में पीने के पानी का संकट है वहां टेंकर भेजे जाते हैं। उसके लिए आप गवर्नमेंन्ट के आवास और निर्माण मंत्री को लिखें ताकि आइन्दा के लिए उस इलाके में पीने के पानी की स्थायी व्यवस्था हो सके।

मैं विशेष रुप से डेजर्ट डवलपमेंन्ट के बारे में कहना चाहता हूं। डेजर्ट डवलपमेंट के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन 50 करोड़ रुपयों से डेजर्ट रोकने की व्यवस्था नहीं हो सकती है। 1977–78 में यह सेन्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीम थी जिसके अन्तर्गत सारी ग्रांट सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट देती थी। राजस्थान गवर्नमेन्ट की इतनी केपेसिटी नहीं है कि वह डेजर्ट को कंट्रोल कर सके। इसके लिए सारी राशि सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट को देनी चाहिए। अगर आप वास्तव में डेजर्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसके विस्तार को रोकना चाहते हैं तो इस 50 करोड़ की राशि को 500 करोड़ कर दिया जाए तभी इसको कंट्रोल किया जा सकता है।

डी० पी० ए० पी० प्रोग्राम के बारे में मेरा कहना है कि जो ड्राट प्रोन एरियाज हैं उनको आप तीन केटेगरीज में बांट दें। सब से पहले जो सर्वाधिक अकाल से ग्रसित हों दूसरी केटेगरी वह हो जो अधिक अकाल से ग्रसित हो और तीसरी केटगरी वह जो सामान्य रुप से अकाल से ग्रसित हो। इस प्रकार से इस समस्या को हल किया जाना चाहिए। मैं अपने यहां की राजस्थान नहर के बारे में विशेष रुप से कहना चाहता हूं। हमारे यहां नर्मदा का भी विवाद है। इसको गुजरात के चीफ मिनिस्टर और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जल्दी से जल्दी तय करें जिससे कि हमारे यहां राजस्थान केनाल और नर्मदा का पानी पहुंच सके और हमारे क्षेत्र को सिंचाई का लाभ मिल सके।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Arjunan. You will not take more than ten minutes.

SHRI K. ARJUNAN (Dharmapuri): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Demands for Grants in

[Shri K. Arjunan]

respect of the Ministries of Agriculture and Rural Reconstruction.

India is predominantly an agricultural country, and agriculture here depends only on the monsoon; in case the monsoon fails, it suffers much. The irrigation facilities in India are inadequate. There is lot of scope for providing irrigation facilities: the waters of rivers can be diverted for irrigation purposes. There are a lot of rivers flowing, but they are not being harnessed.

Regarding Tamil Nadu, the west-flowing rivers can be harnessed and the water diverted towards Tamil Nadu for irrigation purposes. Since the matter concerns two states, Kerala and Tamil Nadu, rightly the Centre can intervene and a settlement can be brought about so that the west-flowing waters can be diverted towards Tamil Nadu: by that, Kerala also, which has a shortfall in food production: can get food grains from Tamil Nadu.

Regarding the Ganga-Cauvery scheme, which has been a long-standing one, it has not even been taken to the stage of investigation by the Centre. The Centre should take the initiative on this. The entire country will get the benefit and will become fertile: it will give job opportunities to a number of persons; India will attain self-sufficiency in food production. India will definitely get stronger in the matter of integrity. 75 per cent of our population depend on agriculture here. In India mostly the hill tribes and the harijans are dependent on agriculture most of whom are agricultural coolies.

MR. DEUTY-SPEAKER: Say agricultural workers.

SHRI K. ARJUNAN: Most of them are agricultural workers. The main purpose of the Government should be to help the agricultural workers to harness the waste waters which are going into the sea. The water can be utilised by the agriculturists so as to make India, a fertile country.

In Tamil Nadu drought conditions prevail—I need not go into details. This prevails to the maximum extent because there is failure of monsoon. Actually, there is no drinking water. Hindu has published an article—I do not exactly remember the date —— stating that the drinking water is supplied through the ration cards. In my constituency, there is a village called Sengagiri where drinking water is supplied to the people. Drought conditions prevail in Tamilnadu. The State Government is not taking step to explain the position to the Central Government in time. Agricultural labourers are suffering without work and food. Because of the failure of the monsoon, they cannot even attend to any other work. They suffer from acute drinking water supply. They cannot even feed their cattle. In Tamil Nadu there is short-fall in food production. The State Government is not concentrating their attention on the drought affected areas. Their attention is only on how to earn money through the spirit scandal, Sathiya Arakattali and compulsory collection from the bus operators.

Their attention is now on how to escape from these.

MR. DEPUTY SPEAKER: Please conclude.

SHRI K. ARJUNAN: Sir, the M.P.s of both Congress (I) and D.M.K. have represented to the Central Government. Thanks to them they sent a team to study the position in the drought affected areas. I request the Centre to give more funds to the drought-affected areas and, at the same time, I request them to direct the State Government to constitute an all-party committee to superavise the workers engaged in the drought affected areas. Because there is no Panchayat Elec-

tion, there is no local body to supervise the work. What they are doing is that they collude with the officials of the local bodies, panchayat unions etc. to give all the works to AIDMK workers/volunteers. Crores of rupees are given to the workers of the AIDMK. These may not help the poorer sections affected by the drought.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now you must conclude.

SHRI K. ARJUNAN: Bore well is made. Corrupt practices are rampant. There is malpractice. This will have to be checked property.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You conclue now because a reasonble time must be given to all.

SHRI K. ARJUNAN: The reason for the failure of the monsoon is because in Tamilnadu, all the forest wealth has been removed by the unsocial elements. I can also say that one of the Ministers in Tamilnadu has nominated several legislators in each district to cut sandal trees and they have been removed from the forest. Village Officers have been sent home and so there is nobody to look after the villages. The trees have been cut, and sent to the depots.

SHRI DIGVIJAY SINH (Surendranagar): Sir, I will be very brief. While supporting the Demands for Grants I would like to make a few suggestions. The first is that the Forest Conservation Act, 1980 which has been very well introduced has just one clause which required to be probed into, namely, the pattern of re-plantation of forest trees. I am firmly against mono-culture. From that point of view we should look at this Act once again.

Sir, in 1952 the National Forest Policy was enunciated in which 22 per cent of the land was to be covered under forests. I think it is high time we revise this and enunciate a new national forest policy going into greater details. As regards social forestry, I think, far more incentives need to be given for village forestry so that this programme is made more effective. There is no proper perspective today on giving forest areas for man-made forests for use of the paper industry. I think a policy needs to be enunciated on those lines. As far as importance of Science is concerned—utilising water hyacinth for paper—I think much more reserach needs to be done and far much more money needs to be invested in biological control of weeds and crop diseases.

Now, Sir, a word about Central Land Use Commission. I have been told that the Government has enunciated a policy of setting up a Central Land Use Commission. As early as 1976 there was a scheme of having State Land Use Boards but with the coming into force of Central Land Use Commission, I think, those State Land Use Boards in each State will be made more effective.

Sir, the national policy for utilisation of marine resources in the effective economic zone needs to be enunciated. It should include things like patrolling, conservation, regulating and development of aqua-culture and fish farming. There is no legislation today as far as the regulation of fishing in either in the inland waters or in the marine areas of India. I think this needs to be done very soon. Sir, the marine national parks which are on the anvil in Lakhsdweep, Gulf of Manner and Jamnagar coasts should be implemented very soon.

MR. DEPUTY SPEAKER: Please conclude.

SHRI DIGVIJAY SINH: Sir, as far as irrigation is concerned there is no proper lining of canals. I think that needs to be attended to especially from the point of view of water logging and alkalinity.

[Shri Digvijay Singh]

Lastly I thank the hon. Minister for having paid heed to my suggestion made last year in respect of Crop Insurance. He has provided Rs. 20 crores for that scheme.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI R. V. SWAMINATHAN): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to speak on fisheries, animal husbandry, dairy and horticulture at this stage. My senior colleague, Rao Birendra Singh, the able Minister will reply on the other subject matters dealt with in the Department of Agriculture. I am grateful to the hon. Members who have made a number of valuable suggestions. They have made many valuable suggestions on the subjects of Fisheries, Animal Husbandry, Dairying, and Horticulture. I take this opportunity of dealing with these points which have been raised by hon. Members. I take Fisheries first. Hon. Members would be glad to know that, in spite of various constraints, today, India stands seventh in the world on total fish production; it is second on Inland Fish production. We are at present one of the largest producers of Shrimps, which form the backbone of our export of fish, valued around Rs. 220 crores annually. As against Rs. 151.24 crores during the Fifth Plan, we have now included an outlay of Rs. 367.71 crores during the Sixth Plan in the State and the Central Sectors on Fisheries.

Marine Fishery forms the major part of our Fisheries Programme.

The production of Marine fish is now about 16 lakh tonnes. The estimated potential roughly is 46 lakh tonnes.

Sir, compared to our coastline of 5650 K. Ms. and the E.E.Z. of 202 Million hectares, our Fleet of Deep-sea Fishing Trawlers, (both in the public as well as in the private sector), of about 75 is very inadequate. This inadequacy is taken advantage of by foreign vessels who poach in our E.E.Z. It is proposed to have by 1985. 350 Deep-sea Fishing Vessels. Sir.

SHRI RANAVIR SINGH (Kaiserganj): Mr. Deputy Speaker, Sir, the Hon. Minister has got a number of Ministers in his Ministry. They are all intervening. Much of the time is taken away in this manner. So, this time should be excluded from our time. This is my request, Sir.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have got to decide it in your party meeting.

SHRI RANAVIR SINGH: Rao Saheb has got largest number of Ministers. All of them are intervening in this manner. Much &of the time is being taken away. This time should be excluded from our time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Actually you have taken more time.

(Interruptions)

SHRI R. V. SWAMINATHAN: I am glad to say that during the last few months. *(Interruptions)*. . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: Not permitted. Don't record. *(Interruptions)***.

SHRI R. P. YADAV (Madhepura): I rise on a point of order. There is no quorum in the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Quorum bell is being rung.

Yes, now there is quorum. Mr. Swaminathan, you may please continue.

---

*Not recorded.

SHRI R. V. SWAMINATHAN: I am glad to say that during the last few months we have taken a number of concrete steps to meet the challenge of deep-sea fishing. The Government has been deeply concerned about poaching by foreign vessels going on in our waters. We have drafted a Bill for regulating fishing by foreign vessels in our waters and we export to introduce the Bill during the current session of Parliament. The Bill provides for heavy penalty and confiscation of poaching vessels.

The Government cannot be oblivious to the interest of fishermen doing fishing on non-mechanised boats, of various types. The model Bill for demarcating fishing zones, between mechanised and non-mechanised boats, which had been circulated earlier, is being pursued with the State Governments, and the question of having a Central Legislation, for such purpose is also under our active consideration.

In order to increase our export earnings, fishing of exportable varieties, is being encouraged, and culture of shrimps, in inland brackish water, is being taken up in the coastal States.

Within the time available, I have tried to give a bird's eye view, of our marine fisheries programme. The recent hike in the cost of diesel has hit the fishing industry, especially the small mechanised fishing boats very adversely. The modalities of giving them some incentive, or relief are being considered.

Now, I come to inland fisheries. Our production in this sector, now is 9 lakh tonnes. The estimated potential of inland fisheries is more than 40 lakh tonnes annually. Our approach is to develop the perennial ponds, tanks, brackish water areas near the Delta area of our rivers, increase the productivity of fish in our reservoirs and adopt more efficient methods of fishing in running waters. The North-Eastern Region, is being given special attention for inland fisheries development.

In order to involve the poorest sections of our rural population, for exploitation of inland fisheries resources through grant, loan and techincal-advice, our scheme of Fish Farmers Development Agency is being expanded. In addition, subsidy for capital as well as recurrent expenditure is available to small and marginal farmers for fisheries development in all I.R.D./S.F.D.A. blocks. We have increased the number of Fish Farmers Development Agency from 50 in the beginning of the last year to the present strength of 98. Under the programme, water areas are given on long-term leases, to individuals and Fishermen's Cooperatives and subsidy and loans are given for development of the tanks, supply of fish seeds, and other inputs through intensive extension machinery.

The main constraint of development of inland fisheries has so far been shortage of fish seeds. This is being tackled by having a chain of hatcheries and fish seed farms run either by the State Governments or Fish Seed Corporations.

Apart from Credit provided under FFDA, the amendment to the Reserve Bank of India Act has placed fisheries on par with agriculture and is eligible for financing at rates applicable for agriculture.

On the marketing side, Government has already carried out a study of three markets, namely, Calcutta, Delhi and Bangalore and all-India market surveys for marine fisheries and Inland fisheries are in progress.

Now, I would like to say a few words about Animal Husbandry. Apart from fish, the milch cattle, poultry piggery, sheep and goat from the most productive assets of our landless rural poor. The value of

(Shri R. V. Swaminathan)

their assets can be increased by helping them, to increase their yield through proper management. The Plan outlay in the Central budget on Anilmal rearing of improved animals are also provided.

For undertaking a massive programme of animal husbandry and dairying, the State Departments of Animal husbandry and Dairy are being strengthened at various levels. The Indian Grassland and Fodder Research Institute at Jhansi and Arid Zone Research Institute, at Jodhpur are developing suitable varieties of fodder and grasses. We have seven regional stations for forage production and demonstration for motivating farmers to take to fodder cultivation as a support to Dairy programme.

At present, the country has about 16,000 veterinary hospitals, dispensaries and mobile units and about 8000 Veterinary aid centres. Thus, every block is covered by more than one such institutions or centres. It is proposed to add 2500 new Veterinary Hospitals and Dispensaries during the Sixth Plan period. Intensive efforts will be made for the control of rinderpest, foot and mouth and other diseas of national importance. I am glad to say that we are at present practically self-sufficient in the production of vaccines. The present level of production of 333 million doses of vaccines wil lbe increased further to 410 million doses by 1985.

Now, I come to dairy. Even though since independence, we have nearly doubled the milk production at 30 million tonnes the per capita availability is very low. It is proposed to increase, the milk production to 38 million tonnes jd gf from Ah duin ted animal husbandry and dairy programmes through cooperative structures of what is known as Anand or Amul pattern. A massive national programme of Operation Flood I has been taken up.

Some reference was made to the lower availability of milk per head. The per capita availability of milk per day has increased from 108 gms in 1970 to 120 gms in 1980. We propose to increase it to 146 gms in 1985. Some hon. Members indicated that our dairy development programme is consumer oriented. I must clarify that the primary objective of our dairy programme is to benefit the rural milk producers through producers cooperative organisations. The cooperatives help the producers in improving the health and productivity of their cattle and remunerative price for their milk. With this direct link between the producers and the consumers, the share of the trade is avoided. Studies have shown that most of the milk producers during the last few years have increased their cash incomes by 50 per cent to 100 per cent

One hon. Member suggested that the milk producer should receive payment for his milk not only on the basis of the fat content but also on the basis of non-fat solids (SNF). Government are of the same view. In fact we have already recommended to the State Governments the two axis pricing formula under which account is to be taken of both the fat and the SNF content of milk.

The Operation Flood I Dairy Project with the four metropolitan cities of Delhi, Bombay, Calcutta and Madras as the marketing area, has been brought to a successful completion. There has been a three-fold expansion in the milk processing capacity of the organised sector in these four cities. A processing capacity of 34 lakh litres of milk per day has been established in 21 rural milk shed areas. Over 10,000 producers' cooperative societies, with a membership of more than 13 lakh farmers, have been set up. The House will be happy to know that the project was

evaluated by a UN Evaluation Mission in the closing stages, of the last financial year, and the mission has expressed appreciation of the performance of the project.

Government now propose to accelerate the implementation of Operation Flood-II, which will have a much larger coverage of 148 cities and 150 milk shed districts and 10 million farmers families. Preliminary discussions between the project authority and the concerned State Governments have been completed in most cases and actual implementation has also been started in six States. We hope that this Integrated National Cattle-cum-Dairy Development Project will show rapid progress during the current year.

Talking of poultry, there has been phenominal increase in egg production from about 7.7 million in 1974 to the present level of 12 million. The improved layer, poultry population, also has increased from 29 million in 1971 to the present level of 40 million. In order to avoid total dependence on foreign source for poultry breeding stock, import of grand-parent, and parent stock, has been banned and development is being done through import of pureline stock only for a limited period. It is expected that this country will be self-sufficient even on pureline stock during the next five years or so. The hatcheries, which are developing pureline stock are being given all necessary assistance. marketing of eggs at the national and regional level, is being undertaking through the National Agricultural Co-operative Marketing Federation which is being encouraged to expand its poultry marketing activities. The question of having a poultry marketing organisation at the national level is under our consideration.

Under the various special programmes, subsidy ranging from 25 per cent to 50 per cent is being provided for setting up of sheds, purchase of chicks and feed costs, etc. to small and marginal farmers and tribals in the setting up of 50 to 200 layers unit per family. Arrangements have been made to provide training to the farmers and provision of loan at 4-1/2 per cent rate of interest for the lower income groups. The private hatcheries, have been instructed to meet the requirements of chicks of small farmers, on priority basis. We have recommended to the State Governments to recognise poultry as an agricultural activity for the purpose of electric tariff etc.

I shall now close my intervention with a few words about horticulture. Horticulture, as a whole, has remained a rather neglected subject. Its importance is, however, obvious. During 1980-81, therefore, an important decision was taken by Madam Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, to create a separate Division of Horticulture, in the Department of Agriculture and Cooperation, for giving whole-time attention to the integrated development of horticulture in the country.

Sir, as the Hon. Members are well aware, there is a well established, positive correlation between the rising level of economic prosperity, and falling percentage of population depending upon land-based agriculture alone. Besides, a marketable surplus of milk, poultry, meat, fish etc. will be generated for them through genetic improvement of the animal wealth, extension services and proper farm management. I am sure this House will give its whole-hearted blessings to this approach and programme. The various suggestions made by the Hon. Members will be considered by the Government in furtherance of the basic objectives, ameliorating the condition of our rural poor—an objective to which let all of us dedicate ourselves.

Sir, I am grateful to you and the hon. Members for giving me a patient hearing.